इंसान कितना भी सुंदर क्यों न हो उसकी परछाई हमेशा काली होती है।
– अज्ञात

कृषि क्षेत्र और इन्फ्रॉस्ट्रक्चर

कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वैकल्पिक ऊर्जा, इन्फार्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नालजी और स्टार्टअप्स को उन्होंने ऐसे स्पॉट्स के रूप में चिह्नित किया जो मौजूदा चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को हमारी आकांक्षा की उड़ान से जोड़ने की कूवत रखते हैं।

भारती शर्मा।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सीआईआई की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में इकॉनमी के उन पांच कारकों की ओर ध्यान खींचा, जो आने वाले समय में सीन बदल सकते हैं। कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वैकल्पिक ऊर्जा, इन्फॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नॉलजी और स्टार्टअप्स को उन्होंने ऐसे स्पॉट्स के रूप में चिह्नित किया जो मौजूदा चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को हमारी आकांक्षा की उड़ान से जोड़ने की कूवत रखते हैं।

इन संभावनाओं को रेखांकित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने इन क्षेत्रों, खासकर कृषि क्षेत्र में प्रस्तावित सुधार का अजेंडा आगे बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। इन बातों की उपयोगिता और उनके द्वारा चिह्नित क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं को भला कौन खारिज कर सकता है, लेकिन असल बात उन एक–दो बड़ी चुनौतियों से निपटने की है, जिसके बगैर बड़ी से बड़ी संभावना भी अभी के माहौल में खुद को साकार नहीं कर पाएगी।

कृषि क्षेत्र और इन्फ्रास्ट्रक्चर में कितने और कैसे सुधार की जरूरत है, इस पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी लगातार बोल रहे हैं, जो बिना किसी अपवाद के हर समस्याग्रस्त अर्थव्यवस्था के सामने ऐसी ही 'रामबाण औषधियां' लेकर उपस्थित होते हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर सरसरी नजर रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि हमारी बीमारी दूर होने की शुरुआत तभी होगी, जब हम अपने बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को पटरी पर लाने की ओर बढ़ेंगे। पिछले कई सालों से हमारी बैंकिंग प्रणाली को तबाह कर रहे बट्टाखाता कर्जे (एनपीए) कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ बड़े कारोबारियों का बैंकों से भारी–भरकम कर्ज लेकर विदेश भाग जाना समस्या का छोटा पहलू है। ज्यादा बड़ा मामला दिवालिया घोषित हो चुके या इसके करीब पहुंच रहे बड़े और मझोले उद्यमों का है, जिनसे सारी कोशिशों के बावजूद कर्जे की वसूली सपना ही बनी हुई है।

यह समस्या कोरोना काल में और ज्यादा गंभीर इसलिए हो गई है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जारी मोरेटोरियम की व्यवस्था के चलते किसी को भनक तक नहीं है कि इस बीच कितना नया एनपीए बैंकों के सिर पर सवार हो गया है। एक बात तो तय है कि लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले से ज्यादा बिगड़ी है। ऐसे में धूर्त और अक्षम कारोबारियों के विपरीत बहुत सारे जेनुइन उद्यमी भी धंधा बिल्कुल न चल पाने के कारण कर्ज वापसी को लेकर हाथ खड़े करने को मजबूर हो सकते हैं। इसके संकेत कई तरफ से मिल रहे हैं।

नौकरी चले जाने, कमाई बंद होने, कारोबार बैठ जाने के कारण रोजमर्रा के खर्च के लिए प्रॉविडेंट फंड और बचत योजनाओं से निकाली गई राशि और पैसा निकालने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सोने का भाव रेकॉर्डतोड़ 52000 रुपये प्रति दस ग्राम के पार चले जाना वित्तीय असुरक्षा का दूसरा नमूना है। ऐसे में आरबीआई की पहली प्राथमिकता देश की बैंकिंग व्यवस्था को बचाने की होनी चाहिए, क्योंकि यहां कोई बड़ा संकट शुरू हुआ तो किसी संभावना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

आकर्षण

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। दिव्य प्रेम का आह्लाद इतना सशक्त होता है कि इसके सामने सारे दुनियावी आकर्षण फीके और स्वादहीन प्रतीत होते हैं। आइए, हम भी अपने अंतर में मौजूद इस दिव्य प्रेम के साथ जुड़ें और सदा–सदा के आनंद व मस्ती की अवस्था को प्राप्त कर लें।

मैं आपसे सहानुभूति रखते हुए एक बात कहना चाहता हूं...यह एक अनुभविक सत्य है कि कभी किसी को मुफ्त की राय या सुझाव नहीं देने चाहिए। इस दुनिया में सुझाव ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हम बड़ी ही दरियादिली के साथ मुफ्त में बांटते हैं, लेकिन जो उस सुझाव को ग्रहण करता है वह उसे कभी समझ नहीं पाता। इसलिए आप कोई अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ। वैसे भी किसी और को अपने साथ होने वाली घटनाओं के लिए दोषी ठहराना बहुत सहज भी है।

संपादकीय

सरकारी शिक्षा का भविष्य

शिक्षा नीति की एक और आलोचना बार–बार सामने आ रही है। वह यह कि अगर निजी शिक्षा संस्थानों का प्रसार ज्यादा होगा तो सरकारी शिक्षा संस्थान, जिनमें गरीब–गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, उनके अस्तित्व पर संकट न पैदा हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूंजी की आक्रामकता पर जरूरी अंकुश लगाने की कोई व्यवस्था हमें करनी ही होगी। बहुत संभव है कि सरकार इस दिशा में संतुलन बनाने की योजना पर काम शुरू कर चुकी हो। नई शिक्षा नीति के पीछे काम कर रहे विजन की तारीफ करते हुए कुछ शिक्षाविद कहते हैं कि इस पर अमल आसान नहीं होगा। सच यही है कि कोई भी नया परिवर्तन लागू करना आसान नहीं होता। उसमें तरह–तरह की बाधाएं आती हैं। पर उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शिक्षा नीति को आकार देने वाली सरकार इसे व्यावहारिक जामा प्रदान करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बाजार और समय की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा को ढालने की एक समय आलोचना की जाती थी लेकिन अब रोजगार और बाजार एक दूसरे से गुंथते जा रहे हैं। ऐसे में आलोचना के रंग–ढंग भी हमें बदलने होंगे। अब विदेशी शिक्षा संस्थानों से डरने की नहीं, उनसे मुकाबला कर भारतीय उच्च शिक्षा को विश्व स्तर पर स्थापित करने की जरूरत है। देखना है कि इसे व्यावहारिक रूप देते वक्त सरकार हमारे शिक्षा संस्थानों के लिए आवश्यक स्पेस बचाने का क्या इंतजाम करती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अपनी सामाजिक संपदा, देशज ज्ञान और लोक भावनात्मकता को आधुनिकता से जोड़कर यह शिक्षा नीति भारत में 'पूर्ण नागरिक' के निर्माण का पथ प्रशस्त कर पाएगी। आत्मनिर्भर भारत अगर बनना है तो ऐसे ही शिक्षित मानुष उसकी आधारशिला बनेंगे।

जैसे, वह एक साथ विज्ञान और संगीत की पढ़ाई कर सके और दोनों उसे रचनात्मक बना सकें, व्यावसायिक लाभ दे सकें। यह शिक्षा नीति भारत में लिबरल एजुकेशन सिस्टम' के दरवाजे खोलती है।

नई शिक्षा नीति

बद्री नारायण।

नई शिक्षा नीति–2020 के भीतर निहित योजनाओं को देखा जाए तो इसमें एक तो शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों से युक्त एक प्रॉडक्टिव नागरिक बनाने की कोशिश है। दूसरा, यह पॉलिसी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा लचीलापन प्रस्तावित करती है, जिससे इसकी जड़ता टूट सके। तीसरा, शिक्षार्थी ने अपना जो भी समय शिक्षा के लिए दिया है, उसका कोई न कोई लाभ उसको जरूर हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। जैसे, वह एक साथ विज्ञान और संगीत की पढ़ाई कर सके और दोनों उसे रचनात्मक बना सकें, व्यावसायिक लाभ दे सकें। यह शिक्षा नीति भारत में लिबरल एजुकेशन सिस्टम' के दरवाजे खोलती है। अपनी 'पाठ्यक्रम अवधि' की व्यवस्था को वह ऐसा बनाना चाहती है जिससे एक संस्थान से दूसरे संस्थान में छात्रों की गतिशीलता बहाल हो सके। पश्चिमी देशों की शिक्षा व्यवस्था के साथ भारतीय शिक्षा व्यवस्था के गहन संवाद की कोशिश भी एनईपी–2020 में दिखाई देती है।

यह शिक्षा नीति एनरोलमेंट दर 100 प्रतिशत प्राप्त करने का वादा कर रही है और समाज के वंचित तबकों को भी शिक्षा के दायरे में समाहित करने के लिए सैद्धांतिक स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता

प्रदर्शित कर रही है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया है कि पूरे देश में 5वीं क्लास तक निश्चित रूप से, 8वीं तक वरीयता के आधार पर और उसके बाद ऐच्छिक आधार पर मातृभाषा और स्थानीय भाषा से छात्रों का संबंध गांव–घर और परिवार में ही नहीं, स्कूलों में भी बना रहेगा।

जैसा कि हम जानते हैं मातृभाषाएं और स्थानीय भाषाएं अपने साथ सामाजिक अनुभव, संवेदना, मूल्य और भावनात्मकता की थाती लेकर चलती हैं। अभी स्कूल में जाने के बाद हमारा संबंध इनसे कम होने लगता है। नतीजा यह कि हम अपने सामाजिक अनुभवों, संवेदनाओं की परंपरा से कटने लगते हैं। अगर भविष्य के शिक्षित मानुष के निर्माण में यह ज्ञान, अनुभव और संवेदनात्मक परंपराएं आधार तत्व की तरह मौजूद रहें तो यह बेहतर नागरिक बनाने के हमारे मिशन को पूरा करेगा।

एनईपी–2020 शिक्षा व्यवस्था में मल्टिपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था कर इसे अत्यंत लचीला बनाने का प्रावधान हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही है। कोई कहीं से भी किसी भी कोर्स में आ सकता है और जा सकता है। छोड़कर जाने के बाद भी उसका वह समय बेकार नहीं जाएगा, ऐसी व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति से विकसित होने जा रही है। यह स्टूडेंट्स के 'फ्यूटिलिटी सिंड्रोम' को खत्म करेगी। छात्र अपना जो भी समय जिस कोर्स में देंगे, उसका कोई न कोई परिणाम उनको मिलेगा, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का वादा यह शिक्षा नीति करती है। स्किल और विशेषज्ञता, दोनों के लिए यह शिक्षा नीति समुचित स्पेस देने की कोशिश करती दिख रही है। तीन वर्ष का अंडरग्रैजुएट कोर्स करने के बाद कोई नौजवान नौकरी या किसी अन्य पेशे से जुड़ सकता है। जो चौथे साल का कोर्स करेगा, वह शोध में दाखिला लेकर किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है।

नई शिक्षा नीति–2020 अनेक संरचनात्मक बदलावों के लिए भी पहल करती दिख रही है। अभी तक हमारे यहां अनेक संस्थाएं शिक्षा के विविध आयामों के लिए बनी हैं।

अष्टयोग- 5134

		3	4		6	7
7	24	2	32	3	41	
	3		5	6		
6	28		36		30	4
		5	6		1	
5	39	7	43	4	25	
4				1		3

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5133 का हल

6	4	1	7	2	5	3
5	33	3	32	1	27	7
4	3	7	5	6	1	2
3	35	2	37	7	32	6
7	4	5	2	3	6	1
2	32	4	36	4	30	5
1	3	6	7	5	2	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

दुनिया अगर बड़ी न हुई होती तो...

मोहन। भारत में शिक्षा की दुनिया अगर बड़ी न हुई होती तो यह व्यवस्था माकूल थी। लेकिन यह बहुत फैल चुकी है। यह आज दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में एक है। ऐसे में इस शिक्षा नीति निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े लोगों का मानना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ही नियामक संस्था होने से भारतीय उच्च शिक्षा के संचालन में आसानी होगी। पश्चिमी देशों की तरह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी अब 'रैंकिंग' पर जोर देकर गुणवत्ता विकसित करने की प्रक्रिया को ज्यादा सक्षम बनाने की कोशिशें इस नई शिक्षा नीति में निहित हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों का देश में आगमन और निजी क्षेत्र के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों का प्रसार भी इस नई व्यवस्था के जरिये आसान होने की संभावना बन रही है। हालांकि विदेशी शिक्षा संस्थानों को भारत में तीव्र प्रवेश मिलने से भारतीय शिक्षा संस्थानों के लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।